Volume-10, No. 1 Feb.-2023, pp. Hin.04-08

चुनाव परिणामों की अस्वीकारोक्ति–लोकतन्त्र के समक्ष उभरती चुनौतीः समकालीन वैश्विक परिदृश्य का अवलोकन

डॉ. रामचन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान,
एस0एम0पी0 राजकीय महिला (पी0जी0) कालेज, मेरठ।

सारांश

विश्व में जब हम राजनीतिक व्यवस्था के इतिहास की बात करते हैं तो हमें अरस्तु द्वारा ईसा पूर्व दिये गये शासन व्यवस्था के वर्गीकरण की याद आती है जिसमें उन्होंने दुनिया के लगभग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने व तुलनात्मक विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में शासन व्यवस्थाओं का सरकुलेशन (परिवर्तन या बदलाव) होता है। उन्होंने बताया कि शासन व्यवस्थाओं के दो रूप होते हैं शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध रूप से आशय जब तक कोई व्यवस्था जनता के हित में कार्य करती है तब तक वह व्यवस्था का शुद्ध रूप होता है और जब वह व्यवस्था जनता के हित में कार्य न करके एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों या एक वर्ग विशेष के हित में कार्य करने लगती है तब वह उसका विकृत रूप होता है।[1] इसी आधार पर विश्व में भिन्न–भिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थायें स्थापित रहीं है। एक समय आया जब विश्व में लोगों की राय या मत को महत्त्व दिये जाने की बात प्रारम्भ हुई और लोकतन्त्र का आर्विभाव हुआ। धीरे–धीरे यह विश्व की आधुनिक राजनैतिक व्यवस्था बन गई। किन्तु पिछले कुछ वर्षों से दुनिया के अग्रणी लोकतांत्रिक देशों में इसका जिस तरह से विरोध प्रारम्भ हुआ है यह चिंता का विषय बनता जा रहा है।

मुख्य शब्द–

मैग्नाकार्टा, परिवर्तन, लोकतांत्रिक, अधिकार पत्र, शासन व्यवस्था, स्वीकारोक्ति आदि।

प्रस्तावना–

ऐतिहासिक दृष्टि से लोकतन्त्र का प्रारम्भ ब्रिटेन में 1215 में आये मैग्नाकार्टा से माना जाता है किन्तु यह केवल सांकेतिक प्रारम्भ ही था और धीरे–धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ। जैसे–जैसे इस व्यवस्था का विस्तार हुआ इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। विश्व का जो भी देश इसको अपनाता वह आधुनिकीकरण का परिचायक कहलाता किन्तु पिछले कुछ वर्षों से इसका भी विरोध विभिन्न रूपों में सामने आया है। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

वास्तव में लोकतंत्र का प्रारम्भ 1688 ईव की ब्रिटेन में हुई 'शानदार क्रान्ति' से माना जाता है जिसके बाद ही वहाँ नागरिक अधिकार पत्र को शासक की स्वीकृति प्राप्त हुई। उसके बाद विश्व के अन्य देशों में भी इसी तरह के अधिकारों की माँग होने लगी। इसका विस्तार अमेरिका में स्वतन्त्रता के लिए हुए आन्दोलन 1775 ईव से और अधिक हुआ। तत्पश्चात् उसी से प्रेरित होकर फ्राँस में स्वतन्त्रता हेतु क्रान्ति (1789.1799) का होना विश्व में लोकतान्त्रिक व्यवस्था के स्वरूप को और अधिक विस्तार एवं मजबूती प्रदान करती है। उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों ने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया। जिसमें भारत सर्वाधिक आबादी वाला लोकतान्त्रिक देश है। इस व्यवस्था को अपनाने वाले सभी बड़े गर्व से यह बोलते है कि हम एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था वाले देश है। जिसको विश्व की आधुनिकतम राजनीतिक व्यवस्था होने का दर्जा प्राप्त है। मोटे तौर पर कारगर लोकतंत्र, के प्रमुख घटक है स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव, खुला और उत्तरदायी शासन, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, लोकतंत्रीय और सिविल शासन। शीतयुद्ध के समाप्त होने के पश्चात् लोकतंत्र एक सार्वभौमिक आदर्श बन गया है। अब सभी देश इसे अंगीकृत करना चाहते है। समकालीन विचारक फ्रांसिस पुकुयामा ने तो उदारवादी लोकतंत्र को मानव शासन का अंतिम

रूप कहा तथा उदारवादी लोकतंत्र की विजय को इतिहास की विजय कहा है।

वर्तमान स्थिति एवं परिस्थितियाँ : 8 जनवरी 2023 को ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में संसद, राष्ट्रपति भवन और सर्वेच्च न्यायालय पर हुए हमले से दो साल पहले अमेरिकी संसद पर हुए हमले की याद ताजा हो गई और एक प्रश्न भी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया कि आखिर चुनी हुई लोकतान्त्रिक सरकार का इस तरह विरोध होना कहीं लोकतन्त्र के अवसान की ओर संकेत तो नहीं कर रहा है। यह केवल अमेरिका और ब्राजील तक ही सीमित नहीं है इसी बीच श्रीलंका में भी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन व प्रधानमन्त्री आवास पर इतनी उग्रता से हमला किया कि उन्हें विदेश में जाकर शरण लेनी पड़ी। भारत में भी विपक्षी दलों द्वारा सत्ताधारी पार्टी या गठबन्धन का हर समय तथा हर मसले पर विरोध करना तथा जनता को उग्र प्रदिर्शनों के लिए उकसाना इसी आरे संकेत करता है।

ब्राजील व अमेरिका में हुए इन उग्र प्रदर्शनों ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर सर्वाधिक आकृष्ट किया है। इन दोनों देशों में घटित इन विरोध प्रदर्शन की घटनाओं में काफी समानता व गहरे सम्बन्ध भी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हर चार वर्ष बाद नवम्बर माह के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को हेाता है। सन् 2020 में यह 3 नवम्बर को हुआ किन्तु उससे पहले ही अक्टूबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के बाद ट्रंप प्रशासन में व्हाइट हाउस में रणनीतिकार रहे स्टीव बैनन के पॉडकास्ट पर एक मेहमान ने कहा था कि ये पूरा मामला ठीक नहीं दिखता'' इस समय तक चुनाव में कुछ भी स्पष्ट नहीं था लेकिन इसके बाद भी बैनन कई हफ्तो तक चुनावों में धांधली की आधारहीन अफवाहों को फैलाते रहे। बैनन के पॉडकास्ट के कई एपिसोड्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये अपने मेहमानों के साथ चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे, यही नही उन्होंने ब्राजीलियन स्प्रिंग हैशटैग को प्रमोट किया। इस सिलसिले में एक मौका ऐसा भी आया जब बोलसोनारो ने हार स्वीकार करने के संकेत दिये किन्तु इसके बाद भी बैनन विरोधी आवाजों को बढ़ावा देते रहे। यहाँ यह स्पष्ट कर देना समीचीन होगा कि स्टीव बैनन वही व्यक्ति है जिन्होंने साल 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान नतीजों पर सवाल उठाने के लिए इसी रणनीति का प्रयोग किया था। इसी के बाद अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को लोगो का विशाल समूह झूठी व अप्रमाणिक अफवाहों से क्रोधित होकर अपने राजनीतिक उद्देश्यों के साथ सरकारी इमारतों की खिड़कियाँ तोड़कर उनमें घुस गया। अमेरिकी संसद पर हुए हमले से एक दिन पहले बैनन ने अपने पॉडकास्ट पर कहा था कल सब कुछ तबाह होने वाला है'। डोनाल्ड ट्रंप की अफवाहें फेलाने वाले दूसरे सलाहकारों की तरह बैनन रविवार को ब्राजील से आती तस्वीरें और वीडियों देखते हुए भी पछतावा करते हुए नजर नहीं आये। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सोशल साइट पर लिखा 'लुला ने ये चुनाव धांधली से जीता था और ब्राजीली लोग ये बात जानते हैं'। इसके साथ ही उन्होंने ब्राजील की सरकारी इमारतों में जबरन घुसने वालों को ''स्वतन्त्रता सेनानी'' करार दिया।

अमेरिकी और ब्राजीली घटना में संबंध : ट्रंप और बोलसोनारो के समर्थकों के आन्दोलन के बीच क्या सम्बन्ध है को बताने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और बोलसोनारो के बेटे की ट्रंप के फ्लोरिडा वाले रिजॉर्ट में हुई मुलाकात का हवाला दिया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य दूसरे समाचार संस्थानों की रिपोर्टस के अनुसार, उस ट्रिप में इक्वार्डो बोलसोनारो ने बैनन और ट्रंप के सलाहकार जेसन मिलर से भी बात की थी। साल 2020 में अमेरिका में हुए चुनाव की तरह ही ब्राजील में हुए चुनाव के आलोचको ने वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने चुनाव में प्रयोग किये गये इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों पर संदेह व्यक्त किया है।

रविवार 8 जनवरी 2023 को दंगाई जिस बैनर को दिखाकर प्रदर्शन कर रहे थे उसमें अंग्रेजी और पुर्तगाली में लिखा था ''वी वांट सोर्स कोड'' वो वास्तव में उन अफवाहो को आधार बना रहे थे कि चुनाव में प्रयोग की गई वोटिंग मशीनो से छेड़छाड़ की गई थी ताकि बोलसोनारो को हराया जा सके। बीबीसी के एक विश्लेषण के अनुसार बड़ी संख्या में ब्राजील के वैसे लोगों के ट्विटर अकाउंट चुनाव के बाद व एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद बहाल कर दिये गये जिनमें चुनाव को नकारने को लेकर अफवाहे फैलाई जा रही थी, पहले इन अकाउंटस पर प्रतिबन्ध लगा था। एलन मस्क ने बिना कोई ब्योरा और प्रमाण दिये यह इशारा किया था कि ब्राजील में ट्विटर के कुछ कर्मचारी राजनीतिक रूप से पक्षपाती नजरिया रखते हैं। अमेरिका में भी ट्रंप के कुछ

विरोधियों ने ब्राजील में मौजूदा अशांति के लिए पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो को उत्तरदायी ठहराया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद और कैपिटल हिल्स दंगे की जाँच करने वाली कमेटी के सदस्य जेमी रस्किन ने अपने ट्विट में ब्राजील में प्रदर्शन करने वालो के बारे में कहा ''ये फास्सिट लोग 6 जनवरी के ट्रम के दंगे की तरह ही'' आचारण कर रहे हैं। जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव से पहले ही अपने समर्थकों से कहा था कि सभी बूथ पर जाकर मतदान करें पोस्टल मतों का प्रयोग न करें, जबकि राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोरोना महामारी के कारण पोस्टल मतों का अधिक प्रयोग करने का आह्वान किया था। इससे यह जाहिर होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप परिणाम आने से पूर्व ही पोस्टल मतों को अवैध ठहराने का मन बना चुके थे। ऐसा ही कुछ ब्राजील के बोलसोनारो के समर्थकों को भी लग रहा है।

श्रीलंका में चुनी हुई सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शनः अमेरिका ओर ब्राजील में ही नहीं श्रीलंका में भी अप्रैल 2022 में चुनी हुई सरकार के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन हुए ओर प्रदर्शनकारियों ने इसका मुख्य कारण वहाँ पर व्याप्त आर्थिक संकट को माना जाता है। आर्थिक संकट ने अब विरोधी लोगो को भी एक कर दिया है। विरोध प्रदर्शन ने अब सिंघली, तमिल और मुस्लिम सभी एकजुट हो गये हैं। लोगों के हाथों में अंग्रेजी तमिल और सिंघनी भाषा के पोस्टर है जिन पर लिखा है 'Go Gota Go' प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि लंबे समय तक राजनेताओं ने तमिल, सिंघली और मुस्लिमों को बाँटकर रखा। अब श्रीलंकाई एकजुट हो रहे हैं तथा राष्ट्रपति सचिवालय के नजदीक प्रदर्शन कर राष्ट्रपति गोटावाया राजपक्षे और प्रधानमन्त्री महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे है। यह प्रदर्शन 9 अप्रैल 2022 से चल रहा था। वहाँ के लोगों को दूध, चावल, रसोई गैस, बिजली, दवायें, पैट्रोल और डीजल जैसी बुनियादी चीजों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुद्रास्फीति की दरें रिकॉर्ड तोड़ अपने उच्च स्तर पर पहुँच गई है और विदेशी मुद्रा की गम्भीर कमी के कारण जरूरी वस्तुओं के आयात में भारी कमी आयी है। मोटे तोर पर श्रीलंका के दिवालिया होने में सरकार की गलत नीतियाँ सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। विदेशी मुद्रा की कमी, ईंधन ओर बढ़ती महंगाई के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट ने श्रीलंका के लोगों को संड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। आर्थिक संकट; महँगाई, मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव, विदेशी मुद्रा भण्डार में कमी, भ्रष्टाचार, सरकारी लेटलतीफी भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में चुनी हुई सरकारों का भी विरोध के प्रमुख उभरते कारण रहे हैं।

भारत में म्टड को लेकर विपक्षी दलों के आरोप व विरोध प्रदर्शनः भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र कहलाता है तो यहाँ यह प्रश्न उठना जरूरी है कि क्या यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है ? इस प्रश्न का उत्तर ढूँढने पर हम देखते हैं कि विगत कुछ वर्षों से भारत में भी लोकतान्त्रिक चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं। यहाँ टैक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं वहीं उसके इस्तेमाल पर गड़बड़ी करने के आरोप भी सरेआम लगने लगे हैं। विगत कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों (उ.प्र., मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, कर्नाटक तथा हरियाणा) में हुए चुनावों और विपक्षी दलों की हार के बाद सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि जब आरोप लगने शुरु हुए तब चुनाव आयोग ने इन मांगो पर ज्यादा कुछ नहीं कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने भी उ.प्र. समेत चार राज्यों में सरकार बनाने के जश्न के बीच इसे विरोधी दलों की हताशा बताया था।

संसद में सरकार की ओर से तत्कालीन केन्द्रीय कानून मन्त्री रविशंकर प्रसाद ने कहा', जब आप चुनाव जीतते हैं तब ई.वी.एम. मशीन ठीक होती है और हारने पर आपको लगता है कि मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि 2006 में चुनाव आयोग ने जब ई.वी.एम. के इस्तेमाल पर सभी पार्टीयों की बैठक बुलाई थी, तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया था।

भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में ई.वी.एम. का समर्थन कर रही है लेकिन वह इसका विरोध करने वाली सबसे पहली पार्टी थी। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा, तब पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ई.वी.एम. पर सवाल उठाये थे। इसके बाद पार्टी ने भारतीय और विदेशी विशेषज्ञो, कई गैर सरकारी संगठनों और अपने थिंक टैंक की मदद से ई.वी.एम. के साथ होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया। इस अभियान के तहत ही सन् 2010 में भा.ज.पा. के तत्कालीन प्रवक्ता और चुनावी मामलों के विशेषज्ञ जी.वी.एल. नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी–''डेमोक्रेसी एट रिस्क,'' कैन वी ट्रस्ट ऑवर इलेक्ट्रॉनिक

वोटिंग मशीन'।[2] इस किताब की प्रस्तावना भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी ओर इसमें आन्ध्र–प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री चंद्रबाबू नायडू का संदेश भी प्रकाशित है। इतना ही नही भाजपा के एक वरिष्ठ नेता डॉव सुब्रमण्यम स्वामी भी ई.वी.एम. इस्तेमाल का जोर–शोर से विरोधकर रहे है। 2009 के चुनावो के बाद, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह आरोप लगाया था कि 90 ऐसी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है जो असंभव है, स्वामी के मुताबिक ई.वी.एम. के जरिये वोटो का 'होलसेल फ्रॉड' संभव है।

अब 2014 के लोकसभा चुनाव को भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस के नेता और तत्कालीन असम सरकार के मुख्यमन्त्री तरूण गोगोई ने भी ईववीवएमव पर सवाल उठाये थें उत्तर प्रदेश में हुए 2017 के विधान सभा चुनावो में मुख्य विपक्षी पार्टी (समाजवादी पार्टी) के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा भी ई.वी.एम. पर खुलकर आरोप लगाये गये 2022 में हुए उ.प्र. विधान सभा चुनावों में भी यह सिलसिला जारी रहा। इससे यह बात साफ होती है कि भारत में जो भी पार्टी चुनावों में विफल होती है वही ई.वी.एम. पर आरोप लगाती रही है। इस बात को दूसरी तरह से कहें तो जनता द्वरा चुने हुए प्रतिनिधियों को ई.वी.एम. के आरोपो के माध्यम से नकारने का यह सिलसिला आने वाले चुनावो में बढ़ता ही जा रहा है।

विश्व में घटी उक्त राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने पर यही प्रतीत होता है कि जिस शासन व्यवस्था को दुनिया की सबसे आधुनिकतम व जनप्रिय व्यवस्था माना जाता है अब राजनीतिक दल और उनके अन्ध समर्थक उसको नकारने लगे हैं। इससे यह प्रश्न उठना या आशंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि लोकतन्त्र का भविष्य अंधकार की तरफ तो नहीं जा रहा है? क्या राजनीतिक दलों के मठाधीश इस लोकप्रिय व्यवस्था को पचा नही पा रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में समाहित है किन्तु अभी तक के घटना क्रम से तो संकेत कुछ ऐसे ही प्रतीत होते हैं।

संदर्भ एवं टिप्पणियाँ :

1. शर्मा, डॉव प्रभुदत्त, 'पाश्चातय राजनीतिक विचारों का इतिहास' कॉलेज बुक डिपो, जयपुर पृव संव. 126
2. नरसिम्हाराव, जीवीएल, 'डेमोक्रेसी एट रिस्क।: कैन वी ट्रस्ट अवर इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन' वेता इंडिया.2010
3. बीथम, डेविड एवं केविन बॉयले, 'लोकतंत्र : 80 प्रश्न और उत्तर' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत 2015 पृव संव.25
4. फुकुयामा, फ्रांसिस, 'एण्ड ऑफ हिस्ट्री : एण्ड द लॉस्ट मैन' द फ्री प्रैस न्यूयार्क 1992 पृव संव.15
5. pic.twitter.com/oRRplmHKxg
6. https://twitter.com/BBCWorld/status/1324504010280308746?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1324504010280308746%7Ctwgr%5Ec5e7129860b3522871bae99deb7a68f4479e8ff2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fhindi%2Finternational-54832938
7. https://www.bbc.com/hindi/international-64213420#:~:text=%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BC%E0%A5%80%E0%A4%B2%20%E0%A4%95%E0%A5%80%20%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%20%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82,%E0%A4%95%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A5%87%20%E0%A4%B8%E0%A5%87%20%E0%A4%9B%E0%A5%81%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%B5%E

0%A4%BE%20%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%B9%E0%A5%88.
8. https://www.bbc.com/hindi/media-64208316
9. https://timesofindia.indiatimes.com/web-stories/world/unrest-in
10. brazil/articleshow/96852828.cms
11. https://www.abplive.com/news/world/explained-why-protest-in-brazil-bolsonaro-supporters-invade-presidential-palace-tensed-situation-2303279
12. https://www.youtube.com/watch?v=Jf0jWuoEtx8
13. https://youtu.be/er9m5XXY-Jg
14. https://www.youtube.com/watch?v=bP8xIgQ9viw
15. https://www.youtube.com/watch?v=hUknxCrWbb0